

नवा भारत



6 नवाचार और युवाओं के लिए नया आकाश



7 भारत का निर्यात 860 अरब डॉलर रिकॉर्ड



8 अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरें...



11 खलील अहमद आईपीएल से हुए बाहर

बिल को राजनीतिक रंग न दें: पीएम

मेरी गारंटी है - निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी

विरोध करने वालों को महिलाओं ने माफ नहीं किया
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं. ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय को समाज की मन स्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैच कर एक राष्ट्र को अमानत बना देती है. एक मजबूत धरोहर तैयार करती है. भारत के संसदीय इतिहास में ये वैसा ही पल है. महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है. संसद के विशेष सत्र में गुरुवार



को हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी लोकसभा में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बिल पर निशाना साधते हुए कहा कि आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले, जब ये विचार सामने आया तभी इसे लागू कर देते. आज हम इसे काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते. आवश्यकतानुसार उसमें समय-समय पर सुधार होते और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिज्ञासु बनते हुए पीएम मोदी ने अपील में कहा कि इस बिल को राजनीतिक रंग न दें.

संसद में प्रियंका गांधी ने की आरोपों की वीअर

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस महिला सांसदों के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन बहस इस पर नहीं बल्कि इस तथ्य पर है कि इस विधेयक में राजनीति की वृद्धि आ रही है. महिलाओं के लिए आरक्षण का कदम वास्तव में केंद्र की एनडीए सरकार का पॉलिटेकनिक टूप कांड है, जिसके जरिए वह चुनावों में लाभ लेना चाहती है. प्रियंका ने महिलाओं के आरक्षण के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का खाका पेश किया. उन्होंने कहा कि देश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस वक्त यह पारित नहीं हो पाया था. उन्होंने बीजेपी पर इस आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया. प्रियंका ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने उस आरक्षण बिल का जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह आधी बात ही बताई.



चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौक जाते...
लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक तंज कसा, जिसे सुनकर वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि आज चाणक्य अगर आज जिंदा होते तो वो भी चौक जाते, आपकी कुटिलता की दाद देते.

ऑकारेश्वर में पांच दिवसीय एकात्म पर्व का शुभारंभ आज

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल. भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक और अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ऑकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल 17 अप्रैल से पांच दिवसीय एकात्म पर्व का मंगलमय शुभारंभ करेंगे. मांथाता पर्वत की कंदराओं में रचे-बसे एकात्म धाम में आयोजित यह महोत्सव दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अजूबा संगम होगा. वैशाख शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित इस अनुष्ठान में देश-विदेश के शीर्ष संत, मनीषी और विद्वान सम्मिलित होकर एकात्मता के वैश्व संदेश को रेखांकित करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव अद्वैत लोक एवं अक्षर ब्रह्म प्रशंसी का लोकार्पण करेंगे साथ ही वैदिक अनुष्ठान में भी शामिल होंगे. इस अवसर पर द्वारका पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के पावन सान्निध्य तथा विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिड़े, स्वामी शारदादेव सरस्वती की गरिमामय उपस्थिति रहेगी.

क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सख्त, 5 विधायक सस्पेंड

चंडीगढ़, 16 अप्रैल. हरियाणा की राजनीति में उस चक्क हलचल मच गई जब कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस-वोटिंग के मामले में अपने पांच विधायकों को निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की सिफारिश पर की गई, जिसे कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी भी मिल चुकी है. पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त संदेश बताने हुए साफ कर दिया है कि संगठन के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जिन विधायकों पर कार्रवाई हुई है, उनमें शैली चौधरी (नारायणगढ़), रेनु बाला (साढ़ौरा), मोहम्मद इलियास (पुहाना), मोहम्मद इस्राइल (हथौन) और जरनैल सिंह (रतिया) शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी की आधिकारिक लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग की. हालांकि, कुछ विधायकों ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन जांच के बाद पार्टी ने कड़ा कदम उठाया है। यह फैसला आने वाले समय में पार्टी अनुशासन को लेकर एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है. निलंबित किए गए विधायकों में शैली चौधरी (नारायणगढ़), रेनु बाला (साढ़ौरा), मोहम्मद इलियास (पुहाना), मोहम्मद इस्राइल (हथौन) और जरनैल सिंह (रतिया) शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी की आधिकारिक लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग की.

एक नजर में 15 लाख की रिश्त के मामले में केस दर्ज

मुंबई. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने महाराष्ट्र में 15 लाख रुपये की कथित रिश्तखोरी के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक अधीक्षक और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान सीजीएसटी टाणे ग्रामीण, आयुवतालय के तत्कालीन अधीक्षक मोहित शर्मा, एक निजी फर्म के मालिक उदय शिवराज कलशेट्टी और एक निजी व्यक्ति किरण व्यास के रूप में हुई है. सीबीआई की मुंबई स्थित प्रशासनिक शाखा की दर्ज प्रार्थिका के अनुसार, यह मामला कर संबंधी मामलों में अंधे नकद निपटान और भ्रष्टाचार के आरोपों वाली एक शिकायत का था. आरोप है कि मोहित शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक अपारिधिक साजिश रची, जिसका उद्देश्य एक फर्म के खिलाफ चल रही जांच को कमजोर करने और उसे जुर्रमान से बचना था.

मतदान करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते

अनिवार्य मतदान की मांग वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, 16 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अनिवार्य मतदान लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो लोग मतदान करने से इनकार करते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि चुनावों में भागीदारी को दमनकारी या बाध्यकारी उपायों से लागू नहीं कर सकते. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागचो और न्यायमूर्ति विपुल पंचोलो की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों से मताधिकार प्रयोग करने की अपेक्षा होती है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया था कि अदालत चुनाव



आयोग को अनिवार्य मतदान के लिए दिशा-निर्देश बनाने और बिना वैध कारण वोट न देने वालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दे. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मताधिकार के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाना जाना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते. न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उठाए गए मुद्दे नीतिगत दायरे में आते हैं और इन पर उचित विधायी और कार्यकारी अधिकारियों (संसद और सरकार) द्वारा विचार किया जाना ही सबसे बेहतर है. पीठ ने दोहराया कि मतदान एक संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक कर्तव्य है, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता.

चौधे और पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भी डीए बढ़ा

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल. राज्य शासन ने उपक्रमों, निगमों, मंडलों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है. इस फैसले से चौथे एवं पांचवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. राज्य शासन द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है. संशोधित दरों के अनुसार पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 323 प्रतिशत तथा चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का 146.5 प्रतिशत हो जाएगा. यह वृद्धि एक जुलाई 2025 से प्रभावशील मानी जाएगी.

अमेरिका ने होर्मुज जलमार्ग में 10 जहाजों को वापस भेजा

इरान ने खाड़ी क्षेत्र में व्यापार को ठप करने की दी चेतावनी
एजेंसी, 16 अप्रैल. होर्मुज जलमार्ग को लेकर अमेरिका और इरान एक-दूसरे के सामने हैं. अमेरिका की सेना ने कहा कि उन्होंने इरानी पोर्ट से निकल रहे 10 जहाजों को रोका और उन्हें वापस भेज दिया. अमेरिकी सेना ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. अमेरिका ने होर्मुज जलमार्ग की नाकाबंदी कर रखी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने एक्स पर लिखा, सोमवार से अमेरिका की नाकाबंदी के बाद एक भी जहाज होर्मुज पर नहीं कर सका है और हमने कम से कम 10 जहाजों को वापस भेजा है. हालांकि अमेरिकी सेना ने जहाजों की संख्या नौ बताई थी, लेकिन आगे यह भी बताया कि 10वें जहाज को अमेरिका के एक गाइडेड मिसाइल डिस्टॉयंग द्वारा वापस इरान की ओर मोड़ दिया गया था. इसी बीच, इरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई तो खाड़ी क्षेत्र में व्यापार को ठप कर दिया जाएगा. इधर, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी कि अमेरिका उन विदेशी संस्थानों पर सेकेंडरी सैंशंसन लगाकर इरान पर आर्थिक दबाव को और बढ़ाने जा रहा है.



वापस भेजा है. हालांकि अमेरिकी सेना ने जहाजों की संख्या नौ बताई थी, लेकिन आगे यह भी बताया कि 10वें जहाज को अमेरिका के एक गाइडेड मिसाइल डिस्टॉयंग द्वारा वापस इरान की ओर मोड़ दिया गया था. इसी बीच, इरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई तो खाड़ी क्षेत्र में व्यापार को ठप कर दिया जाएगा. इधर, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी कि अमेरिका उन विदेशी संस्थानों पर सेकेंडरी सैंशंसन लगाकर इरान पर आर्थिक दबाव को और बढ़ाने जा रहा है.

अमेरिका-इरान शांति समझौते के करीब पहुंचे

सूत्रों के अनुसार अमेरिका और इरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीजफायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अब भी बाकी हैं.

गुस्ताखी माफ

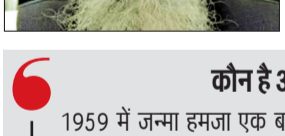
ये बार बार अपनी जात क्यों बता देते हैं ?
मैं अमका जाति का...
मैं किमका कां का...

अशोक चक्र पर गाइडलाइंस बनाने की मांग पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर अशोक चक्र के प्रदर्शन को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के मामलों में अत्यधिक धातुक होने के बजाय रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. मामले की सुनवाई सीजेओ सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बाघची और विपुल एम पंचोलो की पीठ ने की. सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इन बातों को लेकर इतना धातुक होने की जरूरत नहीं है. आपका विचार अच्छा है, आपने अपनी बात रख दी है. अब यह संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला लेते हैं.

लश्कर चीफ आमिर हमजा को मारी गोली

लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने किया हमला
भारत में हुए कई हमलों का मास्टर माइंड है हमजा
इस्लामाबाद, 16 अप्रैल. पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सदस्यों में से एक आमिर हमजा को लाहौर में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी है, उसे फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावरों ने लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर उन पर फायरिंग की. हमला किसने और



क्यों किया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. यह एक साल से भी कम समय में दूसरा मौका है, जब हमजा पर हमला हुआ है. इससे पहले पिछले साल मई में भी उनके घर के बाहर अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मारी थी.

एयरपोर्ट पर दो विमान टकराए

विंगटिप ने विमान के पंख को छुआ
नई दिल्ली, 16 अप्रैल. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक मामूली विमान हादसा सामने आया, जब स्पाइसजेट का एक विमान खड़े अकासा एयर के विमान से टकरा गया. जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब दो बजे स्पाइसजेट विमान के विंगटिप ने ग्राउंड मूवमेंट के दौरान अकासा एयर के स्थिर विमान के पंख को हल्के से छू गया. यह टक्कर बेहद हल्की थी, जिससे दोनों विमानों को मामूली नुकसान पहुंचा. प्रारंभिक जांचकारों के अनुसार, अकासा का विमान उस समय स्थिर था, तभी दूसरी



एयरलाइन के विमान ने उससे संपर्क किया. सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए और दोनों विमानों की जांच शुरू कर दी गई. प्रभावित विमानों को फिलहाल सेवा से हटा दिया गया है ताकि विस्तृत तकनीकी जांच की जा सके.

उपलब्धि पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का लेख किया साझा

सुधार-तकनीक के जरिए नए मानक स्थापित कर रहा रेलवे

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव आया है और यह लगातार सुधार और तकनीक के जरिए नए मानक स्थापित कर रहा है. इस संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा किया, जिसमें बताया कि पिछले एक दशक में स्पष्ट नीति, आधुनिक तकनीक और लगातार निवेश के



जरिए भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारतीय रेलवे के पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है और इसके नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह सेक्टर कैसे सुधार और तकनीक के जरिए नए

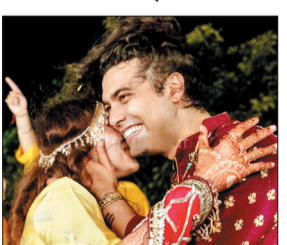
मानक तय कर रहा है. इसमें कहा गया कि करोड़ों यात्रियों के लिए रेल यात्रा कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है. इतने बड़े नेटवर्क में सुरक्षा सिर्फ तकनीकी मामला नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे से जुड़ा मुद्दा है. लेख में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ही 'सेफ्टी फर्स्ट' यानी सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का स्पष्ट संदेश दिया गया था. इसी दिशा में रेलवे ने तकनीकी-आधारित और लगातार निवेश वाली रणनीति अपनाकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को

मजबूत किया है. इसके परिणामस्वरूप देश में ट्रेन हादसों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है. 2014-15 में जहां 135 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं, वहीं 2025-26 में यह घटकर सिर्फ 16 रह गईं, यानी करीब 89 प्रतिशत की कमी आई थी. यह हमी ऐसे समय में आई है जब ट्रेन संवाहन और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी अवधि में 'कंसिक्वेशन एक्सपेडिड इडेव' (प्रति किलोमीटर दुर्घटना दर) भी 0.11 से घटकर 0.01 हो गया है, जो हर किलोमीटर यात्रा के लिहाज से सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित दर्शाता है. 2014-15 में रेल हादसों में 292 लोगों की जान गई थी, जबकि 2025-26 में 16 दुर्घटनाओं में 16 लोगों की ही मौत हुई. रेलवे के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, हर सुबह जब भारत जागता है, तब उसकी रेलें पहले से ही चल रही होती हैं. ऑफिस जाने वाले, छात्र, प्रवासी मजदूर, परिवार और सैनिक समेत 2 करोड़ से ज्यादा यात्री प्रतिदिन ट्रेनों में सफर करते हैं.

जुबिन नौटियाल ने रचाई शादी

बचपन के प्यार संग सात फेरे, जुबिन की सौंठ वेंडिग

देहरादून/मुंबई, 16 अप्रैल. बॉलीवुड के लोकप्रिय सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने फैंस को चौंकाते हुए गुपचुप शादी कर ली है. लंबे समय से इंडस्ट्री के 'एल्लिजबल बैचलर' माने जाने वाले जुबिन ने अपने बचपन के प्यार को जीवनसाथी बना लिया है. खबरों के मुताबिक, यह शादी उत्तराखंड में बेहद निजी तरीके से संपन्न हुई, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. हालांकि, इस शादी को लेकर अभी तक जुबिन की



आरोपों से इनकार किया था, लेकिन जांच के बाद पार्टी ने कड़ा कदम उठाया है। यह फैसला आने वाले समय में पार्टी अनुशासन को लेकर एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है. निलंबित किए गए विधायकों में शैली चौधरी (नारायणगढ़), रेनु बाला (साढ़ौरा), मोहम्मद इलियास (पुहाना), मोहम्मद इस्राइल (हथौन) और जरनैल सिंह (रतिया) शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी की आधिकारिक लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग की.

1 लाख 81 हजार शिकायतों का निवारण

नई दिल्ली. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने बताया है कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कुल 1 लाख 81 हजार 279 शिकायतों का निवारण किया गया. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के काम पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सोपीजीआरएएमएस) की गुरुवार को जारी 47वीं मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। विभाग की विज्ञापित में कहा गया है कि लगातार 45वें महीने केंद्रीय सचिवालय में मासिक शिकायत निवारण का स्तर एक लाख मामलों से ऊपर रहा.